

संख्या: — / VII-2/15 / 88-एम0एस0एम0ई0 / 2015

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,

पटेल नगर, देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 05 अक्टूबर, 2015

विषय:- एम0एस0एम0ई0 विभाग के अधीन मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक:-1549/उ0नि0(5)-12/एम0एस0एम0ई0/अ0वि0/2015-16 दिनांक 14.07.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उत्तराकाशी के गवाणा एवं डुण्डा मिनी औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा तैयार किये गये आंगणनों के तकनीकी सम्परीक्षा (टी0ए0सी0) के उपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि क्रमशः (₹87.04 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत ₹3.25 लाख) ₹90.29 लाख, (₹110.79 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अंतर्गत ₹6.20 लाख) ₹116.99 लाख (कुल धनराशि **₹207.28 लाख**) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ शासनादेश संख्या:-1289/VII-2/89-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 07.09.2015 द्वारा अवमुक्त ₹25.00 लाख की धनराशि का उक्त कार्यों के व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- (ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- (iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाए।
- (iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाए।

- (v) विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vi) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल परिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
- (vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 में दिये गये आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
- (viii) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3 चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय अनुदान संख्या:-23 के लेखा शीर्षक 2851-ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग-00-आयोजनागत, 102-लघु उद्योग, 29-एम0एस0एम0ई0 अवस्थापना विकास निधि, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अंतर्गत ₹25.00 लाख की स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या:-1289/VII-2/89-एम0एस0एम0ई0/2015 दिनांक 07.09.2015 में उल्लिखित सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या:-464/XXVII(2)/2015 दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

संख्या: 2153(1)/VII-2/15/88-एम0एस0एम0ई0/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
- 3 निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4 प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5 कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/देहरादून।
- 6 परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, निर्माण खण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

Dhirendra
(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव।